

राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तारित आदिवासियों की समस्याओं का अविलम्ब समाधान हो- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ओडिशा के मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए बैठक में शामिल

Posted On: 20 JUN 2017 4:13PM by PIB Delhi



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ओडिशा सरकार सकारात्मक पहल कर राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के विस्तारित आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं का अविलम्ब समाधान करे।

आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में ओडिशा के मुख्य सचिव श्री आदित्य प्रसाद, प्रमुख राजस्व सचिव सी एस कुमार, सुंदरगढ़ के जिला कलेक्टर श्री विनीत भारद्वाज एवं आउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्विनी कुमार समेत ओडिशा सरकार, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय तथा राउरकेला स्टील संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।

आयोग ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करवायें कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसी सहकारी समिति अथवा किसी निजी संस्था को उपयोग के लिए नहीं दी गई। साथ ही यह भी जांच की जाए कि संयंत्र को भविष्य में होने वाले विस्तार के लिए वास्तव में कितनी भूमि की जरूरत है तथा संयंत्र के पास अनुपयोगी भूमि कितनी है।

आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे विस्तारित आदिवासियों के रोजगार एवं कल्याण समेत विभिन्न मुद्दों पर कार्यवाही कर स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करें। आयोग ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिए कि सरकार विस्थापितों के लिए आवंटित की गई आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि के स्थायी पट्टे करें। आयोग ने सुंदरगढ़ के जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाए। आयोग ने जिला कलेक्टर एवं संयंत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1993में रोजगार देने के लिए जिन 1098 लोगों को चिह्नित किया गया था उनमें से शेष रहे लोगों को अविलम्ब संयंत्र में रोजगार दिया जाये। साथ ही जिन लोगों को रोजगार दिया गया उनका सत्यापन किया जाये कि क्या वास्तविक विस्थापितों को ही रोजगार दिया गया है।

जितेन्द्र

